

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 27 मार्च, 1987

सं. ओ.वि.सोनी/45-87/12730.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भारत स्टील ट्यूब लि०, गनौर (सोनीपत), के श्रमिक/महासचिव, वी०ए०टी० वर्करज आजाद यूनियन, गनौर, महासचिव, वी० एस० टी० मजदूर संघ, गनौर, महासचिव, भारत स्टील ट्यूब्स कर्मचारी यूनियन, गनौर तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला/मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या संस्था में श्रमिकों के वर्तमान ग्रेड एण्ड स्केल रिवर्राईज करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो किस विवरण से ?
2. क्या संस्था के श्रमिक मकान किराया भत्ता लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?
3. क्या संस्था के श्रमिक एल०टी०ए० लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?
4. क्या संस्था के श्रमिक साल में दो जोड़े जूते लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

कुलवन्त सिंह,

वित्तियुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 19 मार्च, 1987

सं.ओ.वि.रोहतक/30-87/11865.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० निदेशक, प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक, के श्रमिक श्री नफे सिंह, स्वीपर, पुत्र श्री मोहन सिंह, गांधी कैम्प, पटेल नगर, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री नफे सिंह की सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?